कौशल विकास की कठिन चुनौतियां

कौशल विकास योजना तभी कामयाब होगी, जब हम हुनरमंद युवाओं के लिए देश के अंदर और बाहर एक इज्जतदार जिंदगी सुनिश्चित कर सकेंगे।

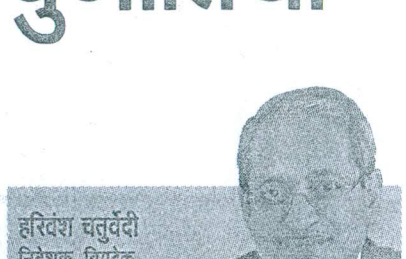

हरिवंश चतुर्वेदी
निदेशक, बिमटेक

चालीस करोड़ भारतीय युवाओं को हुनरमंद बनाने की महत्वाकांक्षी योजना देश का भाग्य बदल सकती है। इस सिलसिले में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन पर ध्यान देना होगा कि यदि चीन दुनिया की फैक्टरी बन सकता है, तो भारत विश्व में मानव संसाधन प्रदान करने वाली धुरी क्यों नही बन सकता? यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले एक दशक से देश में 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' का हल्ला-गुल्ला चल रहा है। यह सही है कि वर्ष 2030 में विकसित देशों में पांच करोड़ नौकरियों के लिए युवा शक्ति की कमी होगी और भारत में पांच करोड़ युवा नौकरियां ढूंढ़ रहे होंगे। हमारे लिए यह कल्पना करना सुखद और आसान है कि 2030 में पांच करोड़ भारतीय युवा पश्चिमी देशों में जाकर बस जाएंगे और वहां की नौकरियां उन्हें मिल जाएंगी। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2030 में पश्चिमी देशों को अप्रशिक्षित भारतीय युवा मजदूरों की जरूरत न होकर विशिष्ट हुनर वाले ऐसे युवा श्रमिकों की जरूरत होगी, जो विदेशी भाषा, संस्कृति एवं जलवायु में काम करने में सक्षम हों।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीसी) की स्थापना यूपीए-2 के कार्यकाल में राष्ट्रीय कौशल नीति के तहत वर्ष 2009 में की गई थी। एनडीए सरकार ने एक अच्छा काम यह किया है कि विभिन्न मंत्रालयों में चल रही बहुत सारी कौशल विकास योजनाओं को कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत लाकर बिखराव को खत्म कर दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल ऋण योजना और कौशल विकास व उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा कर सरकार ने यह एहसास कराया है कि आने वाले दशक में भारत में कौशल विकास पर फोकस बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई कौशल विकास योजना का एक प्रमुख अंग है आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों व अन्य 40 हजार उच्च शिक्षण संस्थानों में एक से छह माह के तकनीशियन एवं वोकेशनल कोर्स चलाया जाना। इन संस्थानों के पड़ोस के उद्योगों का सहयोग भी इन कोर्स के लिए जुटाया जाएगा। इसके अलावा, कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए पांच हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक के कर्ज भी दिए जाएंगे। अनुमान है कि 2022 तक अर्थव्यवस्था के 24 सेक्टरों में 11 करोड़ अतिरिक्त जनशक्ति की जरूरत होगी। रिटेल, रीयल एस्टेट, परिवहन, स्वास्थ्य और ब्यूटी पार्लर से जुड़े क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। पर यह भी एक कटु यथार्थ है कि कृषि क्षेत्र से 2.5 करोड़ लोग गैर-कृषि रोजगार पाने के लिए गांवों को छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। अगर इन 2.5 करोड़ ग्रामीण युवाओं को समय रहते हुनरमंद और रोजगार-योग्य नहीं बनाया गया, तो हम एक बड़ी सामाजिक अस्थिरता और उथल-पुथल को पैदा करने के जिम्मेदार होंगे।

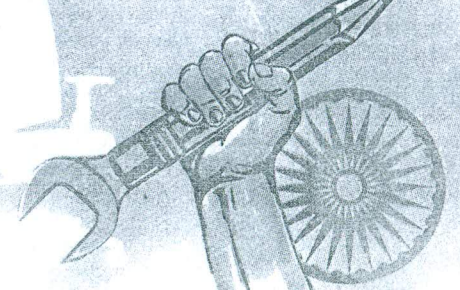

चित्रांकन: डी. श्रीनिवास

केंद्र सरकार ने पिछले एक साल में एक दर्जन राष्ट्रीय स्तर की महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं- स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, वगैरह। इन योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितनी जल्दी हम भारतीय युवाओं को भविष्य में पैदा होने वाली नौकरियों के लिए प्रशिक्षित कर पाते हैं। फिलहाल भारत के श्रमिकों में सिर्फ 3.5 प्रतिशत किसी खास कौशल में प्रशिक्षित हैं, जबकि चीन में 46, जर्मनी में 74 और कोरिया में 96 प्रतिशत श्रमिक प्रशिक्षित होते हैं। इन देशों में पिछले 50-60 वर्षों में सरकार व उद्योगों के प्रयास से ही वहां की श्रम शक्ति हुनरमंद बनी है। पर क्या हम 2022 तक एक-तिहाई श्रमशक्ति को प्रशिक्षित व हुनरमंद बना पाएंगे? सात साल में 40 करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाना असंभव नहीं, किंतु चुनौतीपूर्ण जरूर है। इसके अलावा, भारत पूरी दुनिया में प्रशिक्षित श्रमिक भेज सकता है, पर क्या हम उसे संभव बनाने के लिए जरूरी सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन को तैयार हैं?

कौशल विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करते समय भविष्य में आने वाले खतरों के प्रति भी सचेत रहना होगा। आज जिन हुनर और कौशल के प्रति हम आशान्वित हैं, जरूरी नहीं कि भविष्य में उनकी जरूरत बनी रहे। रोबोटिक्स, इंटरनेट, आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, डाटा-एनेलिटिक्स, ई-कॉमर्स, आदि क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, वे करोड़ों मौजूदा नौकरियों को निगल जाएंगे। क्या ऐसी स्थितियों में हमारे युवा फिर से बेरोजगारी का शिकार नहीं बनेंगे? भारतीय युवाओं को कौशल विकास के नाम पर उच्च शिक्षा से वंचित करना खतरनाक होगा, क्योंकि सीखी हुई खास स्किल्स के अप्रचलित होने पर वे युवा तुरंत नई स्किल्स को रातोंरात नहीं सीख पाएंगे।

इसके अलावा, औद्योगिक जगत की कार्य-दशा पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देश में निर्माण-उद्योगों, खनन, खेती-बाड़ी और भवन-निमार्ण जैसे क्षेत्रों में नियोक्ता और श्रमिकोंके संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं हैं। आज इन उद्योगों में कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ जो बर्ताव होता है, प्रशिक्षित भारतीय युवा उसे स्वीकार नहीं करेगा। एनएसडीसी के चेयरमैन एस रामदोराई का यह कथन सही है कि आने वाले दशक में विश्व बाजार में भारत को सस्ती जन-शक्ति की सप्लाई पर ध्यान न देकर प्रशिक्षित व हाई टेक जन-शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय उद्योगों में स्थायी और ठेके पर नियुक्त श्रमिकों की दोहरी व्यवस्था समाप्त करनी होगी। मेक इन इंडिया और कौशल विकास की राष्ट्रीय योजनाओं की कामयाबी तभी संभव है, जब हम हुनरमंद भारतीय युवाओं के लिए देश के अंदर और बाहर एक इज्जतदार जिंदगी सुनिश्चित कर पाएं।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का बयान है कि 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने की इस मुहिम में नया क्या है, क्योंकि यूपीए-2 सरकार इसे 2009 में ही शुरू कर चुकी थी। यूपीए नेताओं को आत्मालोचना करने की जरूरत है, क्योंकि छह साल पहले यह घोषणा हुई थी कि वर्ष 2022 तक 35 करोड़ भारतीय श्रमिक प्रशिक्षित हो जाएंगे और एनएसडीसी अपने निजी क्षेत्र के सहयोगियों द्वारा 15 करोड़ युवाओं को 2022 तक प्रशिक्षित करा देगा। पी चिदंबरम ने बताया कि पिछले छह साल में एनएसडीसी 160 ट्रेनिंग कार्यक्रमों में 35 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर चुका है। यह 2022 के लिए निर्धारित लक्ष्य का सिर्फ 23 प्रतिशत है। क्या यूपीए नेता इतनी कम सफलता के लिए अपनी पीठ थपथपा सकते हैं?

यह नई सरकार के लिए भी सबक है। 40 करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाने की मुहिम सिर्फ नया मंत्रालय बनाने और 11 मंत्रालयों में बेहतर तालमेल से संभव नहीं होगी। इस पर अनुमानतः आठ लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस हिसाब से फिलहाल 6000 करोड़ रुपये का सालाना का बजट प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरा है। फिर युवा कौशल विकास के प्रशिक्षण पर अपना पैसा और समय तभी लगाएंगे, जबकि नियोक्ता इसके लिए उन्हें बेहतर पारिश्रमिक देने को तैयार हों। अगर नियोक्ता कम वेतन देकर अकुशल श्रमिकों से संतुष्ट हैं, तो कौशल प्रशिक्षण की मांग बहुत कम होगी। यही हाल स्कूलों व कॉलेजों से निकलने वाले युवाओं का है, जो स्किल डेवलपमेंट की बजाय डिग्रियां लेना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके अभिभावक नहीं चाहते कि उनके बच्चे प्लंबर, हेयर ड्रेसर, ड्राइवर, टेलर, नर्स, कंपाउंडर, इलेक्ट्रिशियन या ब्यूटीशियन बनें। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट या आईएएस बनाना कभी भारतीय उच्च वर्ग का सपना था। अब तो समाज के सभी तबके हाथ के हुनर की बजाय, सामाजिक स्टेटस, आर्थिक सुरक्षा और संपन्नता देने वाले पेशों व नौकरियों की तरफ लालायित हैं। यह मामला सोच बदलने का भी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)